इकाई 6 यूरोपीय राजनीतिक लामबंदियां

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि:

- कांग्रेस प्रणाली के गठन के पीछे क्या तर्क था और उसके बाद क्या हुआ;
- ऐसे कौन से घटनाक्रम थे जिनके परिणामस्वरूप सीक्रेट सोसाइटी आंदोलन और 1820 तथा 1830 के दशक के क्रांतिकारी विद्रोह हुए;
- यूरोप के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय आंदोलन कैसे खड़े हुए; और
- वर्ष 1848 की क्रांतिकारी घटनाओं की क्या पृष्ठभूमि थी और उसके क्या परिणाम हुए।

6.1 प्रस्तावना

स्थिरता और शांति के नाम पर यूरोप की महाशक्तियां आस्ट्रिया, रूस, प्रशा और इंगलैंड–नेपोलियन प्रथम के पतन के बाद यूरोप के राजनीतिक नक्शे को फिर से बनाने में जुट गई थीं। इस संदर्भ में गठबंधनों की एक प्रणाली बनी जिसे बाद में 'कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप' (यूरोप का राष्ट्रसंघ) का नाम दिया गया। इस राष्ट्रसंघ के माध्यम से महाशक्तियां यूरोप में शांति को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे से सलाह करते रहने को सहमत हो गई। यह प्रयास भी किया गया कि यूरोप में राजतंत्र की पुरानी व्यवस्था को वापस लाया जाए। वैसे, 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद तथा उदारवाद पहले ही प्रभावी शक्तियां के रूप में उभर चुकी थी। इसके परिणामस्वरूप क्रांतिकारी आंदोलन खड़े हो गए। ये आंदोलन राजतंत्र की सत्ता के खिलाफ थे। 1815 और 1848 के बीच यूरोप में ऐसे अनेक क्रांतिकारी आंदोलन हुए। क्रांतिकारी घटनाओं ने प्रमुख संधियों को पलट दिया और रूढ़िवादी एकजुटता भंग हो गई। इस इकाई में पहले आपका परिचय गठबंधनों की प्रणाली और इसके परिणामों से कराया गया है। इसके बाद इसमें सीक्रेट सोसाइटी आंदोलनों और 1820 तथा 1830 के दशकों की क्रांतिकारी घटनाओं की चर्चा की गई है। अंत में हमने राष्ट्रवादी आंदोलनों के उभरने और 1848 की क्रांति का विवेचन किया है।

6.2 कांग्रेस प्रणाली और उसके परिणाम

वर्ष 1815 में वीएना की कांग्रेस में प्राचीन यूरोपीय व्यवस्था के नायकों ने आस्ट्रिया के चांसलर काउंट मेटरनिख से प्रेरित होकर राष्ट्रवादी तथा उदारवादी आंदोलनों के खिलाफ एक स्थाई अवरोध

खड़ा करने की कोशिश की। मेटरनिख प्रणाली के नाम से मशहूर गठबंधनों की इस प्रणाली का उद्भव स्रोत जार आलेक्सांदर प्रथम के 'पवित्र गठबंधन' (होली अलायंस) और इसके प्रतिद्वंद्वी ब्रिटिश गठबंधन 'चौगुटा गठबंधन' (क्वाड्रपल अलायंस) में देखा जा सकता है। गठबंधन की इन दो अलग–अलग प्रणालियों ने 'कांग्रेस प्रणाली के नाम से मशहूर होने वाली व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रणाली के अधीन 1815 के बाद की अवधि में महाशिक्तयों की कई अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस हुई जिनका मकसद यूरोपीय मुद्दों और समस्यओं पर निर्णय करना था।

वर्ष 1818 के बाद, जब एक्स ला शापेल की कांग्रेस हो चुकी तो यह प्रवृत्ति अधिकाधिक जोर पकड़ने लगी कि जिस किसी भी देश को उदारवादी आंदोलन का खतरा हो वहां की आंतरिक राजनीति में महाशक्तियां हस्तक्षेप करें। एक्स ला शापेल की कांग्रेस में फ्रांसीसी क्षेत्र को खाली किया गया और फ्रांस को यूरोपीय राष्ट्रसंघ में फिर से शामिल किया गया। जार शासन वाले रूस को ब्रिटिश कूटनीतिक सफलता के इस संकेत ने परेशान कर दिया। एक्स ला शापेल में हस्तक्षेप की नीति एक विवादास्पद मुद्दा बन कर उभरी। इस कांग्रेस में उदारवादी आंदोलन से त्रस्त स्पेन में यूरोप के हस्तक्षेप को अंग्रेजी हस्तक्षेप ने रोक दिया। किंतु 1820 में जब ऐसी ही एक विप्लव नेपल्ज में हुआ तो महाशक्तियों ने मेटरनिख की ओर से आई हस्तक्षेप की मांग को स्वीकार कर लिया। इसी के बाद 1820 की ट्रोपी की कांग्रेस में यूरोपीय हस्तक्षेप के इस सिद्धांत को विधिवत समर्थन मिल गया। 1821 की लाइबाख की कांग्रेस में मेटरनिख को निरंकुशतावादी शासनों को फिर से स्थापित करने हेतु नेपल्ज और पीडमांट में हस्तक्षेप की छूट दे दी गई। मेटरनिख प्रणाली की यह सबसे बड़ी जीत थी।

इसमें कोई संदेह नहीं कि 'यूरोप का राष्ट्रसंघ' महाशक्तियों का एक ताकतवर गुट था। किंतु प्राचीन व्यवस्था की जीत इतनी वास्तविक नहीं थी जितनी वह दिखाई देती थी। नेपोलियन के बाद की व्यवस्था को आकार देने वालों ने क्रांति पूर्व की यूरोपीय व्यवस्था को बहाल करने की चाहे जितनी भी कोशिश की हो, अंत में जाकर जो व्यवस्था सामने आई वह प्राचीन तथा नवीन व्यवस्थाओं का मिला–जुला रूप ही थी। नेपोलियन के साम्राज्य ने फ्रांस तथा यूरोप में अन्यत्र कहीं जो अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थाएं खड़ी की थीं उनमें से कुछ को तो पूरी तौर पर समाप्त भी नहीं किया जा सका। हालांकि जमींदार कुलीन वर्ग और धर्म संस्था (चर्च) पारंपरिक वंशों की बहाली से खुद को सशक्त महसूस कर रहे थे, फिर भी बहाल राजतंत्रों के लिए जनता की भावनाओं की अनदेखी करना अब भी संभव नहीं था। ये वंश किसी न किसी रूप में जनता का राजनीतिक समर्थन बनाने की आवश्यकता के प्रति सचेत हो गए। यह सब इस बात का अनिवार्य परिणाम था कि 1815 के शांति स्थापक अपनी प्रजाओं को उदारवाद, राष्ट्रवाद तथा क्रांतिकारी राजनीतिक विचारधाराओं से प्रदूषित होने से बचाने के लिए, बहाल राजतंत्रों के भीतर, पर्याप्त साधन नहीं ढूंढ सके। जल्दी ही जो उपाय किए गए उनके विरूद्ध बनने वाले दबाव इतने कठोर हो गए कि इन राज्यों तथा दक्षिण–पश्चिमी एवं दक्षिण–पूर्वी यूरोप के अनेक भागों में उदारवादी तथा राष्ट्रीय आंदोलनों के उठ खड़े होने पर ये 'पुनरूद्धार' (बहाली) के बाद कुछ ही वर्षों के भीतर टूट कर बिखरने लगे। इन आंदोलनों के लिए वे विचार अत्यधिक प्रासंगिक बने रहे जो कि फ्रांसीसी क्रांति ने पहले ही प्रस्तुत कर दिए थे। वास्तव में तो 'पुनरूद्धार' को उलटने के लिए 1815 और 1848 के बीच जो क्रांतिकारी उथल–पुथल हुई उसके तीन क्रमिक चरणों के दौरान इन विचारों को फिर से लागू किया गया। इनमें से प्रत्येक चरण में क्रांतिकारी अनुभव में तीन सूत्र निहित रहे जिसका सहारा आंदोलनकारियों ने उस तूफानी दौर में लिया जिसका अंत 1815 के 'पुनरूद्धार' को पलटने में हुआ। ये 'सूत्र' थे जनवादी आवरण में राजतंत्र को स्वीकारने वाला नरमपंथी संविधानवाद, लोकतंत्र के छोर पर खड़ा क्रांतिकारी गणतंत्रवाद, और भविष्य के समाजवादी विचारों की पहले से अपेक्षा करने वाला अपूर्ण समतावाद।

किंतु, 1815 और 1848 के बीच पुनरूद्धारित अथवा बहाल शासनों के प्रति विरोध की प्रकृति में बहुत अहम बदलाव हुआ। 1820 के दशक में जो प्रतिपक्ष कुलीन समर्थक तथा षडयंत्रपूर्ण लगता था और जिसके बारे में ऐसा सोचा जाता था कि व्यापक समाज में उसकी जड़ें ही नहीं हैं, वही 1848 में आकर अनेक राजनीतिक जन आंदोलनों से जुड़ गया। किंतु, इस प्रक्रिया में प्रतिपक्ष खुद भी विभाजित हो गया। उनके भिन्न विचारों की रूपरेखा तो वास्तव में बहुत पहले ही दिखाई देने लगी थी। प्रतिपक्ष के मुख्य तत्व वे उदारवादी थे जो राजतंत्र को तो सह लेते थे किंतु इस बात के लिए उत्सुक थे कि निरंकुशतावाद का सुधार हो जाए और वह एक संवैधानिक राजतंत्र का रूप ले ले। इस प्रकार के उदारवाद का प्रतीक फ्रांस में फ्रांस्वा गीजो था जो लोई फीलिप के ऑर्लियनी राजतंत्र में लगातार बनने वाली सरकारों में किसी न किसी रूप में शामिल रहा। किंतु वहीं वामपंथी उदारवादी भी थे जो केवल अमीरों और चर्च के ही नहीं अपितु राजतंत्र की संस्था के ही खिलाफ थे। जिन अतिशय राजभक्तों की धीरे–धीरे सत्ता में वापसी हो रही थी उनके विरुद्ध प्रतिपक्ष में इस

क्रांतिकारी वामपंथी रूझान ने क्रांति की यादों का सहारा लिया। उनके लिए प्रतिनिधि सरकार ही पर्याप्त नहीं थी; वे चाहते थे कि ऐसी सरकार गणतंत्र से भी नाता जोड़े। बेंजमन कांस्टैंट जैसे व्यक्तियों ने कूलीनतंत्री प्रतिक्रिया के आतंक के बारे में लिखा। उग्र सुधारवादियों (क्रांतिकारियों) के अतिरिक्त फ्रांस में समाजवादियों का एक छोटा सा गुट भी था। सैं–सीमौं ने अपने आस–पास अनुयायियों की अच्छी–खासी भीड़ जमा कर ली थी। ये लोग न केवल पुनरूद्धारित शासनों के आलोचक थे अपितु बुर्जुआ व्यक्तिवाद से भी उन्हें उतनी हीं चिढ़ थी। वे एक ऐसे समतावादी गणतंत्र की स्थापना का स्वप्न देखते थे जहां असमानताओं को दूर करके एक तर्कसंगत समाज का निर्माण किया जा सके। 'पुनरूद्धार' के प्रति यह चिढ़ फ्रांस में तो सबसे अधिक थी ही, यूरोप के अन्य देशों में भी कम नहीं थी, और व्यापार चक्र के दौरान समय–समय पर जो आर्थिक संकट की स्थिति बनी उससे पैदा होने वाले जन असंतोष ने तो इस चिढ़ को और प्रबल कर दिया। हालांकि कुलीनतंत्र समर्थक संविधानवादी तो जन साधारण को लेकर हमेशा संदेह की स्थिति में रहे, फिर भी जन साधारण की और अवहेलना करना संभव नहीं था क्योंकि 'पुनरूद्धार' के विरूद्ध होने वाला संघर्ष गंभीरतापूर्वक शुरु किया गया था।

वर्ष 1815 की घटनाओं के तुरंत बाद जो परिणाम सामने आए उनमें पुनरूद्धार विरोधी राजनीति का मुख्य रंगमंच स्पेन रहा, जहां सेना के अधिकारियों और उदारवादी राजनीतिज्ञों ने मिलकर पुनरूद्धारित निरंकुशतावाद के विरूद्ध एक सशक्त आंदोलन चलाया। उदारवादियों को आशा थी कि वे 1812 में त्याग दिए संविधान को लागू करवा लेंगे, किंतु नए शासन ने ऐसा करने से मना कर दिया। गठबंधन में उनके साथी, उदारवादी रूझान वाले कनिष्ठ सनिक अधिकारियों ने पुनरूद्धारित शासन के विरूद्ध अनेक घोषणाएं कर डालीं। फिर मेसनिक तथा सैनिक लॉज की तर्ज पर सीक्रेट सोसायटी (गुप्त संगठन) बनीं तो इस प्रतिपक्षी राजनीति ने धीरे–धीरे षडयंत्र का रूप धारण कर लिया।

6.3 'गुप्त संगठन' आंदोलन

गुप्त संगठन आंदोलन यूरोप में हुई विशेष घटना थी। हर कहीं, इस प्रकार के गुप्त षडयंत्रकारी संगठन बनने का आंशिक कारण पुनरूद्धार कालीन शासनों का संगठित राजनीति पर प्रतिबंध लगाना था। दीक्षा समारोहों, सोपानबद्ध सदस्यता, गुप्त प्रतीक एवं संकेत वाले ये उग्र सुधारवादी गुप्त संगठन कभी–कभी सीधे मेसनिक लॉजों की उपज होते थे। कभी–कभी तो ये संगठन उन गुप्त दक्षिणपंथी संगठनों की खिलाफत के लिए बनाए जाते थे जिनका उदय एक प्रकार की अति राजभक्ति के सहारे 'पुनरूद्धार' को मजबूत करने के लिए हुआ था।

इन गुप्त संगठनों के विविध आयाम भी थे। बहुधा तो ये गुप्त संगठन यूरोप में सक्रिय एक व्यापक उदारवादी आंदोलन के अपेक्षाकृत अधिक क्रांतिकारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे, और उनका मुख्य राजनीतिक उद्देश्य था संवैधानिक सरकार का गठन। यह बात पुर्तगाल के संबंध में सही थी जहां पोंबाल की प्रबुद्ध निरंकुशता पहले ही सुधार कर चुकी थी। पोंबाल सम्राट जॉन का एजेंट था, जो स्थाई रूप से ब्राजील में रहने लगा था। गुप्त संगठन आंदोलन ने 1820 में और भी जोरदार कार्रवाई को प्रेरित किया। उस वर्ष स्पेन के उदाहरण से प्रेरणा लेकर उदारवादियों ने एक सैनिक टुकड़ी से गठजोड़ कर एक उदारवादी संविधान की मांग कर डाली। इससे बाध्य होकर राजवशं को कम से कम कुछ आधे–अधूरे उपाय करने पड़े। फ्रांस में नेपोलियन के प्रति अपनी भावनात्मक निष्ठा बनाए रखने वाले गणतंत्रवादी फ्रांसीसी 'कार्बनारी' के मुख्य तत्व होते थे और बार-बार सत्ता हथियाने की योजना बनाते रहते थे। 1820–21 के आसपास कुछ कनिष्ठ सैनिक अधिकारी भी इस षडयंत्र में शामिल हो गए और उन्होंने एक विद्रोह की योजना बनाई जो सफल नहीं रही। गुप्त संगठनों में महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में फ्रांसीसी समाजवादी, विशेषकर सैं-सीमों के अनुयायी शामिल थे।

इटली में नेपोलियन के कब्जे के समय में ही गुप्त राजनीतिक संगठन उभर चुके थे। इनका उदय आंशिक रूप से फ्रांसीसी आक्रमण से निबटने के तरीके के रूप में हुआ था। अन्य आदर्शों के अतिरिक्त, इन गुप्त संगठनों में राष्ट्रवादी लामबंदी के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुप्त संगठन इतावली 'कार्बनारी' था (यह 'कार्बनारी' संगठन 1811 के आसपास गठित होने वाला एक इतावली क्रांतिकारी गुट था जिसका उद्देश्य था इटली को एक सूत्र में बांधना और एक गणतंत्र की स्थापना करना।) कार्बनारी की स्थापना सिसिली में हुई थी। म्यूरा के फ्रांसीसी शासन के विरोध में स्थापित इस संगठन का उद्देश्य था समूचे इटली में एक राष्ट्रीय संवैधानिक सरकार के

लिए काम करना। इसके बाद यह आंदोलन नेपल्ज में फैल गया। उत्तरी इटली में आदेलफ्या नाम का एक और गुप्त संगठन था, जिसकी स्थापना 1796 में जैकबिन क्रांतिकारी जाक बाबफ के सहयोगी ब्वॉनारॉत्ती ने की थी। 'पुनरूद्धार' के दौरान इन गुप्त संगठनों की गतिविधियों ने इसलिए जोर पकड़ा क्योंकि सिसिलि में बूरबौं परिवार के शासकों की और पड़ोसी इतावली राज्यों की सरकारों की दमनकारी नीतियां चल रही थीं। राष्ट्रवाद का उदय धीरे–धीरे वैचारिक प्रेरणा के एक अन्य स्रोत के रूप हुआ।

'पुनरूद्धार' के विरोध में होनेवाली लामबंदी के इस शुरुआती दौर में, जैसी कि पुनरूद्धारित शासनों को आशंका थी, कुलीन वर्गीय राजनीति और जन असंतोष का गठजोड़ नहीं हुआ। 1820 में स्पेन तथा पुर्तगाल और दो सिसिली के दोनों क्षेत्रों में होने वाले संवैधानिक आंदोलन, अथवा 1821 के पीडमांट और यूनान के विद्रोह भी सारे के सारे कुलीनतंत्र से जुड़े मामले थे जिन्हें सेना के वर्गों का तो समर्थन निश्चित रूप से प्राप्त था, किंतु साथ ही नरमपंथियों तथा क्रांतिकारियों की अंदरूनी फूट और जनता का समर्थन न होने के कारण ये कमजोर भी पड़ गए। इस तरह की कमजोरियों के कारण ही 'यूरोपीय राष्ट्रसंघ' की ताकतें विद्रोह से प्रभावित देशों पर अपनी इच्छा लादने में अपेक्षाकृत सफल रहीं। आमलोगों की तमाम शिकायतों के बावजूद ये षडयंत्रकारी संगठन क्योंकि अंततः कोई जन आंदोलन खड़ा करने में सफल नहीं हो पाए, इसलिए पुनरूद्धारित शासनों के लिए इस प्रकार की लामबंदियों पर अंकुश लगाना और भी आसान हो गया। 1823 में मैड्रिड विद्रोह की पृष्ठभूमि में जब सेना के उदारवादी अधिकारियों ने सत्ता पर कब्जा करना चाहा तो कांग्रेस प्रणाली का प्रतिनिधित्व करने वाली फ्रांसीसी सेना ने स्पेन में हस्तक्षेप करके फार्डिनैंड को वापस गद्‌दी पर बैठा दिया। इसी तरह की घटना 1820 के दशक के प्रारंभ में इटली में हुई। कई विद्रोह हुए जिन्हें आस्ट्रीआई सेनाओं ने दबा दिया। महाशक्तियों ने 1814 के समझौते को बनाए रखने का वादा किया था और यह स्वाभाविक ही था कि उन्होंने कुलीन क्रांतिकारियों की इन गतिविधियों का जवाब हस्तक्षेप से दिया, जिसका समर्थन ट्रोपो ओर लाइबाख की कांग्रेस ने किया था। लाइबाख में 1821 में प्रति क्रांतिकारी गठजोड़ ने दो सिसिलियों के राज्यों के रूढ़िवादी शासन को सहारा देने के लिए आस्ट्रीआई हस्तक्षेप का समर्थन किया। एक वर्ष बाद वेरोना में इन शक्तियों ने 1820 में शुरू हुए उदारवादी विद्रोह को दबाने के लिए फ्रांसीसी हस्तक्षेप का समर्थन किया। इतालवी प्रायद्वीप में 1820–21 के दौरान गुप्त संगठनों द्वारा कई विद्रोह संचालित किए गए। स्पेन की तरह ही इन विद्रोहों में भी कुलीन जन का ही हाथ था। कभी–कभी तो ये तत्व सेना के अंदर के होते थे। इनका उद्‌देश्य होता था कि एक संवैधानिक सरकार को लागू किया जाए। नेपल्ज में उदारवादी विद्रोह की शुरुआत जुलाई 1820 में सैनिक और गैर–सैनिक कार्बनारी इकाईयों ने की। नेपल्ज में विद्रोह होने के एक पखवाड़े बाद पालेर्मो में अपने आप ही विप्लव हो गया। मार्च 1821 में आंस्ट्रीआई सेना ने इन विद्रोहों को आसानी से दबा दिया। 1820 का पीडमांट का विद्रोह इतालवी मुद्‌दों से प्रेरित था, किंतु नरमपंथियों तथा उग्र सुधारवादियों के बीच एकमत न होने से यह कमजोर पड़ गया था। नरमपंथियों ने तो सम्राट को इस बात के लिए मनाने का प्रयास किया कि वह गद्‌दी के उत्तराधिकारी कर्लोस आल्बेर्तो के करीबी सैनिक तथा गैर– सैनिक अधिकारियों के समर्थन वाले संविधान को मंजूरी दें। विक्टर इमैनुएल को संविधान की मंजूरी के लिए मना लिया गया, किंतु आस्ट्रीआई सैनिकों की नज़दीकी तथा सम्राट के पूरे अधिकारियों को बहाल करने के लिए आक्रमण के लगातार खतरे के चलते स्थिति बिगड़ गई। मार्च 1821 में, जब नेपल्ज में उदारवादी विद्रोह पिट गया तो पीडमांट की कार्बनारी इकाईयों ने एक कामचलाऊ सरकार बना ली और एक संविधान की घोषणा भी कर दी। इस विद्रोह को भी एक बार फिर बाद में आस्ट्रीआई सैनिकों ने दबा दिया। इस प्रकार के दमन की गहनता अलग–अलग राज्यों में सचमुच अलग–अलग थी, किंतु समूचे इटली में उदारवादी क्रांतिकारियों पर इसका विध्वंसकारी प्रभाव हुआ, जबकि उसी दौरान फ्रांस में अति राजभक्ति उठान पर थी।

व्यापक यूरोपी संदर्भ में, गुप्त संगठनों की गतिविधियां सचमुच नवोदित राष्ट्रवादी राजनीति का एक अंग बन गई, और इनके नतीजे पूरी तौर पर 1830 के दशक में सामने आए। तब तक, राष्ट्रवाद यदि कहीं अत्यंत स्पष्ट रूप से परिभाषित हुआ तो वह सांस्कृतिक स्वायत्तता के बारे में देखे जाने वाले अनेक रूमानी स्वप्नों में था। फ्रांसीसी आक्रमण ने निश्चित रूप में शताब्दी के प्रारंभिक दौर में राष्ट्रवादी भावनाओं को उकसाया। इटली और जर्मनी में बड़ी राजनीतिक इकाईयों का नक्शा बनाने के अर्थ में नोपोलियन काल की संस्थाओं ने भी सकारात्मक प्रभाव डाला। यह एक सुविदित तथ्य है कि नेपोलियन का आक्रमण तो इतालवी 'रीसोर्जीमेंतो' (इटली की मुक्ति तथा एकता के लिए 19वीं शताब्दी में हुआ आंदोलन) अथवा जर्मन बुद्धिजीवियों की 'लोक भावना' की तलाश का संदर्भ रहा

था। फिर भी 1830 के दशक से शुरू होकर बाद तक चलने वाली यूरोप की राजनीतिक उथल–पुथल इस प्रकार की अपरिपक्व भावनाओं को मूर्त रूप देने में सफल रही।

बोध प्रश्न 1

1) पांच वाक्यों में, 'कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप' के गठन के कारणों को स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

....

....

2) गठबंधन प्रणाली के विफल होने के लिए उत्तरदायी कुछ कारकों के बारे में बताइए। 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

3) संक्षेप में गुप्त संगठन आंदोलनों का महत्व समझाइए। 10 वाक्यों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

6.4 उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे तथा चौथे दशक के क्रांतिकारी आंदोलन

उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक के मध्य के आसपास रूस में विफल दिसम्बरी विद्रोह द्वारा तथा अपेक्षाकृत सफल यूनानी विद्रोह के साथ क्रांति का बुखार नए सिरे से चढ़ा। रूस में, जारशाही का अंत चाहने वाले उग्र सुधारवादियों और रूस में गणतांत्रिक बदलाव ने स्वयं को गुप्त संगठनों में गठित कर लिया। उत्तर का एक संगठन था जिसका ठिकाना सेंट पीटर्सबर्ग में था और इसका दक्षिणी संगठन उक्राइन के तूलोजिन नगर में अवस्थित था। इनमें सैनिक अधिकारियों का बोलबाला था। ये संगठन मात्र संवैधानिक विचारों से संतुष्ट नहीं थे, अपितु वे तो एक समतावादी तथा गणतांत्रिक बदलाव की आशा लेकर संविधानवाद से भी आगे जाने की आकांक्षा रखते थे। ये दिसम्बरी लोग थे जिन्होंने दिसम्बर 1825 में सैनिक तख्ता पलटने का प्रयास किया था। यह वह समय था जब जार की मृत्यु ने सेंट पीटर्सबर्ग में सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसा दिया था। रूसी हथियारबंद फौज ने इस विद्रोह को आसानी से तितर–बितर कर दिया जबकि कुछ दिनों के बाद उक्राइन में हुई इसी तरह की एक और विद्रोहपूर्ण कार्रवाई को इसी प्रकार दबा दिया गया। कर्नल पेस्टल समेत सभी विद्रोही नेताओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया और अन्य अनेकों को देश निकाला देकर साइबेरिया भेज दिया गया।

लगभग उसी समय बनने वाले राजतंत्र के गठबंधन से घातक समझौता करने वाला यूनान का विद्रोह अपेक्षाकृत अधिक सफल रहा। प्रारंभ में, विदेशी बंदरगाहों में रहने वाले धनी यूनानियों ने 'हिताइर,

नाम का गुप्त संगठन बना लिया था और यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की योजना भी तैयार कर ली थी। मार्च 1821 में, इतालवी राज्य के विद्रोह कर देने के साथ ही, यूनान में भी विद्रोह हो गया। किंतु, विद्रोहियों को डैन्यूब नदी के थाले में गैर–यूनानी निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस आंदोलन को तब मजबूती मिली जब यह मुख्य भूमि में फैला। 1882 के प्रारंभ में, इपीडॉरस की यूनानी असेम्बली ने यूनान की आजादी का ऐलान कर दिया। यूनानी संघर्ष में भयंकर मार–काट का सहारा लिया गया और यह उस समय और भी भीषण हो गया जब तुर्की के सुलतान महमूद ने मिस्र के महमद अली से मदद की माग की। महमद अली ने इस मौके का फायदा उठाते हुए यूनान पर आक्रमण कर दिया। प्रारंभ में तो, मेटरनिख ने यूनानियों को बागियों की श्रेणी में रखा और उनके प्रति उदासीनता ही दिखाई। किंतु, बाद में जब इस्तांबुल में यूनानियों का कत्ले आम हुआ तो तुर्की सुल्तान को ईसाईयों के पूजा स्थलों को नष्ट करने के लिए लताड़ दी गई। कुछ समय तक तो, मेटरनिख राजतांत्रिक व्यवस्था पर अधिक जोर देकर यूनानियों के प्रति किसी भी प्रकार का समर्थन जताने से कतराता रहा, किंतु 1826 में स्थिति बदलने लगी। पहले, प्राचीनता की याद जागने वाले 'फिलहलेनिक' (यूनान–बंधु) आंदोलन के शुरू होने से यूरोप में यूनानी मसले के प्रति व्यापक सहानुभूति बन गई। यूरोपीय कुलीन जन अनेक 'यूनान–बंधु' समुदायों से जुड़े थे। इस तरह, तुर्की राजतंत्र ने हिंसक दमन का चक्र चलाया, उससे यूरोपवासियों की भावना को आघात पहुंचा। शायद इसी कारण अप्रैल 1826 में, इंगलैंड और रूस में यूनान को लेकर एक समझौता हो गया, हालांकि बालकंज में दोनों के हित टकरा रहे थे। इस समझौते के तहत, यूनान को तुर्की सम्राज्य के भीतर अच्छी खासी स्वायत्ता दे दी गई। एक लंबे समय से तुर्कों का समर्थन करती आ रही फ्रांसीसी सरकार को भी अपनी नीतियां बदलनी पड़ गई, जिससे कि जुलाई में अंगरेजी-रूसी संधि हुई और इस संधि में इन तीनों ताकतों ने सह वचन दिया कि वे यूनान के साथ मुक्त व्यापार संबंध स्थापित करेंगे और यह वादा भी किया कि जब तक तुर्की द्वारा दमन बंद नहीं होता वे यूनान के पक्ष में सैनिक समर्थन भी करेंगे। तीनों ताकतों ने भूमध्य सागर में अपने बेड़े भेज दिए और इसके बाद इनकी नौसेनाओं ने अक्टूबर 1827 में नावारीनो की खाड़ी में तुर्की–मिस्त्री बेड़े को नष्ट कर दिया। नवारीनो की लड़ाई से भड़ककर सुल्तान ने ईसाई राज्यों के विरूद्ध जिहाद का ऐलान कर दिया। जब बदले की कार्रवाई में रूस ने तुर्की पर जंग का ऐलान कर दिया तो इंगलैंड के कान भी खड़े हो गए, किंतु फ्रांस की मध्यस्थता ने स्थिति को संभाल लिया और उस क्षेत्र में रूसी हस्तक्षेप को स्वीकृति मिल गई। अंत में एक कठिन युद्ध के बाद, रूस को तुर्की पर रणडिनॅ की संधि थोपने में सफलता मिल गई। इस संधि के तहत तुर्की ने सार्बिया, डैन्यूबी राज्यों तथा यूनान की स्वायत्ता को स्वीकार कर लिया। बाद में, 1830 में, लंदन की संधि के तहत यूनान की पूर्ण आजादी को मान्यता मिल गई।

इस सब का परिणाम यह हुआ कि मेटरनिख प्रणाली पूरी तौर पर ध्वस्त हो गई, हालांकि आस्ट्रिया ने जैसे–तैसे इटली और बालकन्ज में अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखा। मेटरनिख हालांकि वैधतावाद को जुनून की हद तक मानता था, फिर भी वह तुर्की राजतंत्र के विरूद्ध यूरोपीय गठजोड़ को रोक नहीं पाया। अंत में, क्रांतिकारी विद्रोह की ताजा घटनाएं हुई तो इस प्रणाली को ध्वस्त होने में तनिक भी देर नहीं हुई। एक स्तर पर, फ्रांस तथा यूरोप के अन्य भागों में जो क्रांतिकारी स्थिति थी वह भीषण एवं व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक उथल–पुथल के एक सामान्य दौर की देन थी। परिणामस्वरूप, संसदीय प्रतिनिधित्व के विवादास्पद मुद्दे पर विद्रोहियों और राजतंत्र समर्थकों के बीच टकराव होने के कारण राजनीतिक उथल–पुथल का जो दौर चला तो आम जनता भी राजनीतिक कार्रवाई के समर्थन में उठ खड़ी हुई। फ्रांसीसी उदारवादी कुछ समय से यह शिकायत करते आ रहे थे कि राजतंत्र छल–बल से उन्हें उनके निर्वाचन अधिकार से वंचित करना चाहता है और उनका आरोप था कि सरकारी अधिकारी राजभक्तों की जीत पक्की करने के लिए मतदाता सूचियों में हेर–फेर कर रहे थे। इस प्रकार की धोखाधड़ी के खिलाफ विरोध की नीति 1827 में प्रसिद्ध विद्वान फांस्वा गीजो के नेतृत्व में बनी। मतदाताओं को मतदान के नियमों की जानकारी देने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, पेरिस में एक संचालक समिति का गठन किया गया और पूरे फ्रांस में स्थानीय समितियां गठित की गई। इसी पृष्ठभूमि में नवम्बर 1827 में एक आम चुनाव हुआ जिसमें जितने राजभक्त जीत कर आए उतने उदारवादी भी जीते। मार्तीन्याक की नई सरकार उदारवादियों से मेल–मिलाप की इच्छुक रही, क्योंकि 1829 तक उदारवादी संसद में बहुमत में थे। फिर भी, स्थानीय परिषदों के सुधार के बारे में अलग–अलग विचार होने के कारण सरकार और उदारवादियों में टकराव हो गया। कर व्यवस्था के मुद्दे पर भी दोनों के बीच असहमति उभरी, और ऐसा विशेषकर 1829 की गर्मियों में मार्तीन्याक के उत्तराधिकारी अति राजभक्त प्रधानमंत्री पॉलीन्याक के काल में हुआ। जबकि पॉलीन्याक के चयन की आलोचना हुई तो संसद के अधिवेशन को बुलाने में हुई देरी भी एक विवादास्पद मुद्दा बन गया। मार्च 1830 में

जब विलम्बित सत्र शुरु हुआ तो संसद को जल्दी ही भंग कर दिया गया क्योंकि चैम्बर ऑफ डिप्टीज ने पॉलीन्याक सरकार में अविश्वास का एक अभूतपूर्व प्रस्ताव पेश कर दिया। किंतु जुलाई 1830 में होने वाले चुनावों में उदारवादियों का प्रतिनिधित्व 220 से बढ़ कर 274 हो गया। बदले की कार्रवाई में, जुलाई के अंत में, फ्रांसीसी सरकार ने अध्यादेश पारित करके उदारवादी अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, संसद भंग कर दी और मतदाताओं की संख्या घटाकर एक चौथाई कर दी। फिर नए चुनाव कराए गए जिनमें वोट का अधिकार केवल धनी लोगों को दिया गया।

इस घटना पर खुली प्रतिक्रिया हुई और उसने जल्दी ही 'अवरोधकों' के माध्यम से प्रतिरोध का रूप ले लिया। 1830 में ये अवरोधक विद्रोह का प्रतीक बन गए। यह सब उस आर्थिक संकट के चलते संभव हुआ जिसने पिछले तीन वर्षों में पेरिस की सड़कों को दस्तकारों के विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बना दिया था। विरोधों ने जल्दी ही अवरोधकों का रूप ले लिया तो लड़ाई शुरू हो गई और तीन दिनों तक चलती रही। इस लड़ाई में क्रांति को दबाने के लिए तैनात किए गए सिपाही भी विद्रोहियों के साथ हो गए। जुलाई की क्रांति बहुत कम समय तक चलने तथा जल्दी ही निपट जाने वाली घटना थी। पुनरूद्धारित राजशाही अपने आपको उदारवादी सांसदों, पेरिस की आम जनता और क्षुब्ध सिपाहियों के गठजोड़ से बचा नहीं पाई। एक कामचलाऊ सरकार का गठन किया गया और 30 जुलाई को सम्राट के रिश्ते के भाई ऑर्लियन्स के ड्यूक को राज्य की गद्दी संभालने को कहा गया। अगस्त के पहले सप्ताह में, फ्रांसीसी जनता की ओर से एक मुकुट आर्लियन्स के ड्यूक को पेश किया गया। फ्रांस में, 1830 की क्रांति एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के साथ पूर्ण हुई।

फ्रांसीसी मिसाल तो संवैधानिक तथा उदारवादी आकांक्षाएं रखने वाले यूरोपीयों के लिए एक प्रेरणा साबित हुई। फ्रांसीसी उदाहरण से प्रोत्साहित होकर बेल्जियमवासी भी डच लोगों के विरूद्ध खड़े हो गए। पोलैंड वालों ने अपने रूसी आकाओं के विरूद्ध विद्रोह कर दिया। बेल्जियमवासी तो एक स्वाधीन राष्ट्र राज्य को बनाने में सफल हो गए जबकि पोलैंड का विद्रोह विफल रहा। इटली में कार्बनारी ने देश को एक करने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। जब जुलाई की क्रांति ने फ्रांस में एक संवैधानिक शासन की स्थापना करवा दी तो इटली के लोगों को भी आस्ट्रीया का प्रभुत्व समाप्त करने के लिए फ्रांस की हस्तक्षेप विरोधी नीति में आशा दिखाई दी किंतु उनकी यह आशा मिथ्या साबित हुई। बहरहाल, फरवरी 1831 में मोडेना में एक विद्रोह के बाद पोप की अधीनता वाले राज्यों में संवैधानिक आंदोलन हुए। बॉलॉन्या में मार्च 1831 में एक संविधान की घोषणा की गई। नेपल्ज और पीडमांट में घोर दमन के चलते उथल-पुथल नहीं फैल पाई। आस्ट्रीआई सेना के हस्तक्षेप ने इन योजनाओं पर पानी फेर दिया। लूई फिलीप की फ्रांसीसी सरकार ने इटली में बोनापार्टवाद की वापसी से भयभीत होकर एकदम यह मान लिया कि आस्ट्रीआई हस्तक्षेप आखिरकार एक पारिवारिक मामला था। मार्च में जब आस्ट्रीआई सैनिक इतालवी विद्रोह को कुचलने के लिए आए तो बॉलॉन्या की कामचलाऊ सरकार ने हथियार डाल दिए और हर प्रकार से अंधकारपूर्ण इस परिदृश्य में, फ्रांस के बाहर अगर कहीं कोई ठोस सफलता हासिल की गई तो वह थी स्पेन में। सितम्बर 1832 में, उदारवाद की भावना को स्वीकारते हुए स्पेन में एक उदारवादी सरकार का गठन किया गया और उसके साथ ही स्पेन के निष्कासितों को आम माफी की घोषणा भी की गई। किंतु, 1830 की क्रांति अपने आप में महत्वपूर्ण होते हुए भी अठारह वर्ष बाद होने वाली एक अपेक्षाकृत व्यापक तथा प्रभावशाली क्रांति का पूर्वाभ्यास मात्र था।

6.5 राष्ट्रवादी आंदोलन

उन्नीसवीं शताब्दी के पांचवे दशक में राष्ट्रवाद प्रमुख राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा। इसके प्रभाव में यूरोपीय उदारवाद ने भी काफी क्रांतिकारी रूप धारण किया। फ्रांस में राष्ट्रवादी भावनाओं ने नेपोलियन के बारे में इस मिथ्या धारणा को जन्म दिया कि बोनापार्ट फ्रांसीसी जनता में एकता बनाने के लिए वापस आएगा। आर्लियन्स राजशाही के समय के फ्रांसीसी प्रतिपक्ष ने भी व्यापक मताधिकार सुधारों की मांग उठाई जिससे की आम फ्रांसीसी को भी नागरिकता दी जा सके। 1848 की क्रांति की पूर्व बेला में मताधिकार के विस्तार की इस मांग के समर्थन में दावतों का आयोजन किया गया। 1848 में फ्रांसीसी क्रांतिकारी आलेक्सांद्र लेद्रू-रोलां ने एक कदम आगे जाकर सार्वभौमिक पुरुष-मताधिकार (यूनिवर्सल मैनुहड सफ्रेज) की हिमायत कर दी और इससे यह संकेत मिला कि राजनीतिक बहस में एक केंद्रीय मुद्दे के रूप में संवैधानिक सुधार धीरे-धीरे अब लोकतांत्रीकरण के प्रति एक गंभीर संवेदनशीलता को स्थान दे रहा था। मध्य एवं पूर्वी यूरोप में होने वाली राष्ट्रवादी लामबंदी भी इसी उभरती हुई लोकतांत्रिक विचारधारा से बच नहीं सकी जिसकी

अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रांतिकारी राजनीति में हुई। अगर हम पूर्व और दक्षिण में इटली और जर्मनी की ओर चलें तो समान नियति की भावना मिलेगी जो राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए उपयुक्त थी। राजनीतिक राजभक्तों को अब भी, विशेषकर देहातों में, वंशवाद, क्षेत्रवाद और दोष स्वीकार पद्धति (कन्फेशनलिज्म) के बल पर मोड़ना संभव था; फिर भी, राष्ट्र एक सशक्त प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरा। चिंतकों ने राजनीतिक विभाजन की विद्यमान स्थिति में एक अखंड राष्ट्र राज्य के उभार को देखना शुरू कर दिया। अनेक जर्मनवासियों को इस तथ्य पर खेद होने लगा कि उनके देश इतने छोटी–छोटी इकाईयों में बंटे हुए थे। मध्य एवं पूर्वी यूरोप के अन्य देशों की तरह यहां भी इस प्रकार की भावनाएं उदारवादी राजनीति को आकार देने लगीं। उदारवादी हर जगह नरमपंथी और उग्रपंथी वर्गों में बंटे हुए थे। जर्मनी में नरमपंथी उदारवादी तो एकीकरण के लिए होने वाले आंदोलन में जर्मन राजकुमारों के नेतृत्व को लेकर आशावान थे, जिसका दारोमदार काफी कुछ प्रशा की पहल पर था। प्रशा ने 1834 में प्रकट तौर पर जर्मनी के भीतर आर्थिक एवं वाणिज्यिक अवरोध तोड़ने के लिए जिस 'जोलवरन' की स्थापना की थी, उससे उदारवादी तत्व एकीकरण की प्रशा केंद्रित योजना के औचित्य के बारे में आश्वस्त हो गए थे। वैसे प्रशा के राजतंत्र की इस प्रकार की किसी भी योजना में तब तक कोई रूचि नहीं थी जब तक कि प्रशा के वंशधरों के हित इसके अनुकूल नहीं बैठते। किंतु उनके कुछ मित्रों ने आस्ट्रिया के लिए भी ऐसी ही अपेक्षाएं बांध रखी थीं। अब क्योंकि आस्ट्रीया की पहली चिंता यह थी कि वह एक बहुराष्ट्रीय समाज को बनाए रखे, इसलिए इस रणनीति के कोई परिणाम देने की संभावना नहीं थी।

इतालवी उदारवादियों के पास ऐसा कोई राज्य नहीं था जिस पर वे अपनी आशाएं केंद्रित कर सकें, सिवाय पीडमांट की राजशाही के जिनकी आस्ट्रिया के हैप्सवर्ग वंश के साथ पुराने समय से पारिवारिक शत्रुता चली आ रही थी। किंतु यथार्थ में प्रशा की तुलना में पीडमांट एक छोटा और अपेक्षाकृत शक्तिहीन राज्य था। इसका परिणाम यह रहा कि कुछ इतालवी बुद्धिजीवियों ने पोप के नेतृत्व में एक इतालवी संघ का प्रस्ताव तक रख दिया। किंतु पोप ने लगातार उनकी इस कोशिश में सहयोग करने से मना करके उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया।

किंतु, जर्मनी और इटली के उग्र सुधारवादियों का इस विषय में अलग ही विचार था कि राष्ट्रीय एकता कैसे कायम की जाए। वे राजशाही सरकारों को एकीकरण की राजनीति का रोड़ा मानते थे; उनके विचार में इन सरकारों को उखाड़ना ही एकीकृत राष्ट्र–राज्य की पूर्वशर्त थी। इटली में उग्रपंथी राष्ट्रवाद का महानतम प्रवर्तक गुसप्पै मैज़ीनी (1805-1872) हुआ। गुसप्पै ने पहले 1827 में कार्बनारी की एक शाखा में भाग लिया था, किंतु उनमें उद्देश्य की स्पष्टता न पाकर उसका जल्द ही उनसे मोहभंग हो गया। उसका मानना था कि आस्ट्रीया के प्रभुत्व से इटली की मुक्ति पूरी तौर पर कुलीन जनों के विशेषाधिकार और पुरोहित वर्ग के अधिकारों को समाप्त होने पर ही निर्भर थी। इसी उद्देश्य को सामने रखकर उसने 1832 में 'युवा इटली' की स्थापना की और एकजुट इतालवी राज्य के लिए गणतांत्रिक किस्म की सरकार का स्वप्न देखा। 1834 में सेवॉय में एक सशस्त्र विद्रोह के विफल हो जाने के बाद मैज़ीनी निर्वासित होकर लंदन चला गया। किंतु, इटली में राजनीतिक कलह 1830 के दशक के अंतिम वर्षों और 1840 के दशक में बार–बार उभरता रहा, हालांकि आम जनता की सक्रिय भागीदारी न होने के कारण आंदोलन का अब भी संकीर्ण आधार था। 1848 की घटनाओं ने इस स्थिति को बदल दिया और मध्य एवं दक्षिणी यूरोप के अन्य भागों में भी राष्ट्रवादी लहर के लिए नई संभावनाएं खोल दीं।

यही वह काल था जब यूरोप के पूर्वी छोरों पर स्थित आस्ट्रीआई साम्राज्य की छोट–छोटी राष्ट्रीयताओं ने अपनी ऐतिहासिक एवं लोक परंपराओं को पुनर्जीवित कर राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान को जोरदार ढंग से सामने रखना शुरू कर दिया था। इनमें से अधिकांश स्लावी राष्ट्रीयताएं थीं जैसे – चेक, स्लोवाक, क्रोएट, स्लाव, उक्राइन तथा रूमान्या। इन क्षेत्रों के साहित्यिक संगठन हालांकि एक छोटे से बुद्धिजीवी कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, फिर भी उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाना शुरू कर दिया। अक्सर ये भावनाएं अधिसंख्य किसानों में परंपरावाद के अवरोध से टकराती थीं। इस मामले में पोलैंड और हंगरी के लोग कुछ अधिक भाग्यशाली थे। वहां प्रांतीय 'डाइट' जैसी संस्थाओं ने राष्ट्रवादी लामबंदी के लिए केंद्रीय संस्थाओं का काम किया। पोलैंड और हंगरी में एक राष्ट्र–राज्य की लालसा के साथ–साथ लोकतांत्रीकरण, सामंतवाद का उन्मूलन, और सीमांत क्षेत्रों तथा स्थानीय सरकारों पर केंद्रीय नियंत्रण लगाने के व्यापक कार्यक्रम भी चलाए गए। किंतु दोनों ही मामलों में इस आंदोलन को किसानों की उदासीनता और साम्राज्य के हंगरी वाले हिस्से में रहने वाली उन छोटी राष्ट्रीयताओं की ओर से रूकावट का सामना करना पड़ा जिन्हें मैगयार जाति की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रभुता की बात पसंद नहीं थी।

1) यूनानी विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर 10 वाक्यों में दीजिए।

....

....

....

....

....

2) फ्रांस की जुलाई क्रांति के विषय मे पांच वाक्यों में लिखिए।

....

....

....

....

....

3) इटली और जर्मनी में राष्ट्रवादी आंदोलनों के उदय की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। 100 शब्दों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

6.6 वर्ष 1848 की क्रांतिकारी घटनाएं

वर्ष 1848 में यूरोप ने 'जनता के युग' में सतर्कतापूर्वक प्रवेश किया! राजनीतिक लामबंदियों की प्रकृति चाहे जो भी रही हो, ये लामबंदियां जनता के बीच समर्थन प्राप्त करने लगीं। ऐसा उन गुप्त संगठनों की राजनीति की कमियों को मिटाने के प्रयास में हुआ जिन्होंने शताब्दी के प्रारंभ में राजनीतिक उथल–पुथल के विभिन्न दौरों में अपना दबदबा बनाए रखा था। आर्थिक तंगी ने लामबंदी की इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से योगदान दिया। आमतौर पर, यूरोप के अधिकांश भागों में 1830 के दशक से गरीबी बढ़ गई। आंशिक रूप में यह एक कृषि प्रधान निर्वाह अर्थव्यवस्था से औद्योगिक पूंजीवाद वाली अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण की गंभीर समस्या का अनिवार्य परिणाम था। अक्सर ही किसान लोग बाजारोन्मुख कृषि को विनाशकारी मानते थे और जब–तब बिचौलिये व्यापारियों के दमनकारी व्यवहार की शिकायत करते थे। शहरी दस्तकार कारखानों के सस्ते माल से होड़ न कर पाने के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले कारखानों को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानने लगे थे। दो क्रांतियों के बीच बुनकरी, निर्माण तथा छपाई के धंधों में लगे दस्तकारों और कारीगरों ने रूक–रूक कर होने वाली हड़तालों और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और बाद में 1848 में शहरी इलाकों में होने वाले क्रांतिकारी विप्लवों में निर्णायक भूमिका अदा की।

स्थानीय सामाजिक संघर्ष की पृष्ठभूमि में, 1845 और 1847 के बीच के वर्ष विशेष रूप से कठिन थे, और इसका कारण था खराब फसल तथा आर्थिक मंदी। 1845 में आलू की फसल चौपट हो जाने के कारण खाद्यान्न की भारी कमी हो गई, और उसके बाद 1846 में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण अनाज़ की फसल भी खराब हो गई। इस स्थिति के कारण खद्यान्नों की जो कीमतें चढ़ीं थी उसके कारण कई जगहों पर खाद्य दंगे हो गए। इस संकट को आर्थिक मंदी ने और भी गंभीर कर दिया और शहरों में बेरोजगारी फैल गई।

यथार्थ में, आर्थिक संकट के कारण जब लोगों के रहन–सहन का स्तर गिरा तो वे क्षुब्ध हो गए और इससे राजनीतिक संकट और बढ़ा। फिर भी, क्रांतिकारी राजनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण एक तत्व था यूरोपवासियों की बेहतर राजनीतिक चेतना; क्योंकि पहले की अपेक्षा मध्य उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोपवासियों को और अच्छी शिक्षा प्राप्त थी। कुछ लोगों ने तो वास्तव में शताब्दी के मध्य के आसपास 'एक शैक्षिक तेजी' के बारे में लिखा भी; और अनेक समकालीन तो शिक्षा के बढ़ते स्तर और एक विद्रोह तेवर के बीच संबंध देखने से नहीं चूके। इतालवी शिक्षाविद गुस्पे मैज़ीनी ने शैक्षिक सुधारों पर अपने एक परचे में तो एक ऐसी प्रणाली की मांग कर दी जो "जनता के आंदोलन" को रोक सके, शिक्षितों की संख्या को सीमित रखे, उन्हें नेक और शांत बनाए, उन्हें अनुपयोगी और हानिकारक बनने से रोके।" देहाती इलाकों में सार्वजनिक शिक्षा के प्रस्तावित विस्तार के बारे में एक आस्ट्रिआई कुलीन जन का जवाब थाः "क्या हम देहातों में स्कूल खोलेंगे, जिससे कि किसान हमारे खिलाफ सरकारी अधिकारियों से शिकायत कर सकें ?"

यदि हम यूरोप के क्रांतिकारी अनुभव की विविधताओं पर विचार करें तो हमें लगेगा कि 1848 की क्रांति एक बहु–आयामी घटना थी। 1848 के यूरोप के विद्रोहों की शुरुआत स्विटजरलैंड के गृह युद्ध से हुई जिसमें क्रांतिकारी रूझान वाले प्रोटेस्टैंट कैंटन रूढ़िवादी कैथोलिक कैंटन से भिड़े। दोनों का यह टकराव 1847 में अपने चरम पर पहुंच गया, और उसके साथ ही राजनीतिक टकरावों की उस श्रृंखला की शुरुआत हुई जिसे इतिहासकार आमतौर पर '1848 की क्रांति' शीर्षक के अन्तर्गत रखते हैं। इस लड़ाई में अंततः जीत क्रांतिकारी रूझान वाले प्रोटेस्टैंट कैंटनों की हुई, क्योंकि रूढ़िवादी कैथोलिक कैंटनों को बचाने की मेटरनिख की कोशिश सफल नहीं हो पाई। स्विटजरलैंड की घटनाओं से यह बात स्पष्ट हो गई कि स्थापित व्यवस्था के रक्षकों में क्रांति की लहर को रोकने की सामर्थ्य नहीं थी।

क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत जनवरी 1848 में सिसिली में हुई, जहां षडयंत्रकारियों के एक गुट ने पालेर्मो की प्रांतीय राजधानी में विद्रोह की योजना बनाई। 1848 की स्थितियों में इस विद्रोह का प्रभाव और भी विस्फोटक हुआ और यह दक्षिण में इटली की मुख्यभूमि तक फैल गया। दो सिसिलियों के राज्य की राजधानी नेपल्ज में लड़ाई सड़कों पर पहुंच आई, उसके बाद ही सम्राट ने एक उदारवादी संविधान लागू करके क्रांति के आगे समर्पण किया। फरवरी 1848 में पीडमांट और टसकनी में भी घटनाओं ने यही रूप लिया। बाद में मार्च में मेटरनिख के पतन की खबर से भड़क कर उत्तरी इटली ने आस्ट्रीआई प्रभुत्व को उतार फेंकने की कोशिश की।

विद्रोहों की श्रृंखला में अगला निर्णायक दौर पेरिस में आया जहां 1847 में शुरू हुए दावत अभियान का स्थान सड़क छाप प्रदर्शनों ने ले लिया। अवरोधक बनाए गए, और विद्रोहों को कुचलने के लिए तैनात किए गए सिपाही खुद विद्रोहियों में जा मिले। इस स्थिति के चलते सम्राट लूई फीलीप को अपनी गद्दी छोड़–छाड़ कर देश से भाग जाने को बाध्य होना पड़ा। 24 फरवरी 1848 को क्रांतिकारी जन समुदाय की ऐसी मांगों के जवाब में गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। मार्च में यह संक्रमण दक्षिणी एवं पश्चिमी जर्मनी में फैल गया। उसी महीने में म्यूनिख में भी विद्रोह हुआ और उसके बाद ऐसी ही घटनाएं वीएना, क्रेको, मीलान और बर्लिन में भी हुई, जिनमें अवरोधकों के दोनों ओर विद्रोहियों और हथियारबंद सिपाहियों के बीच वही जाना–पहचाना टकराव हुआ।

इसी स्थिति में राजनीतिक बदलाव हुए। प्रशा और बावेरिया के राजतंत्रों ने अपने रूढ़िवादी मंत्रियों को बरखास्त करके उनकी जगह उदारवादियों को नियुक्त कर दिया। प्राचीन व्यवस्था का महान प्रतीक मेटरनिख तो निर्वासित होकर लंदन चला गया। सम्राट फर्डिनैंड ने हिचकिचाहट के साथ वीएना में उदारवादी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी। वेनिस और मीलान की कामचलाऊ सरकारों ने आस्ट्रिआई राज से अपनी आजादी की घोषणा कर दी और कहा कि वे एक संयुक्त इतालवी राज्य का हिस्सा बनना चाहते हैं। हंगरी की राजधानी में नई सरकार ने साम्राज्य के भीतर ही अपनी स्वायत्ता का दावा किया।

जर्मनी में स्थिति इटली से भिन्न रही, जहां पीडमांट के शासक ने आस्ट्रीआई कब्जे के ध्वस्त होने का लाभ उठाते हुए एकीकरण के लिए युद्ध शुरू कर दिया था। उत्तरी इटली में एकीकरण के लिए होने वाला आंदोलन शांतिपूर्ण और संसदीय ढंग से चलता रहा। जर्मनी के विभिन्न राज्यों के संसदीय डिप्टियों का एक दल उदारपंथी एवं उग्रपंथी प्रतिपक्ष के प्रतिनिधियों की हैसियत से फ्रैंकफर्ट ऑन मेन में मार्च 1848 में जमा हुआ। इन लोगों ने एक संवैधानिक राष्ट्रीय सभा के लिए चुनावों की अपील की। इस संविधान सभा को एक संयुक्त जर्मन राष्ट्रीय राज्य के लिए एक संविधान तैयार करना था। इसे जर्मन राज्य के नवगठित शासनों की भी सहानुभूति मिलने की संभावना थी। इस तरह बाद में मई चुनाव हुए और फ्रैंकफर्ट राष्ट्रीय संसद ने विचार–विमर्श शुरू कर दिया। वैसे,

उन्हें चेक राष्ट्रवादियों का विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि चेक राष्ट्रवादियों को भय था कि जर्मनी कहीं मध्य यूरोप पर आधिपत्य न कर ले। सुदूर पूर्व में हंगरी की डाइट ने भी कोसूट के नेतृत्व में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने नागरिक स्वतंत्रता को लागू किया, और कैथोलिक पुरोहितों के लगाए अवैध करों और दासता को समाप्त कर दिया। इसके बाद एक उदार मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का निर्णय किया गया। हालांकि इनमें जायदाद की योग्यता को बनाए रखा गया, फिर भी अमीर वर्ग को मिले विशिष्ट विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, एक स्वायत्तशासी हंगरी राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। यह सरकार साम्राज्य के ढांचे के भीतर ही बनी और उसने वीएना स्थित केंद्रीय शाही नौकरतंत्र के नियंत्रण से मुक्ति का दावा कर दिया तथा हंगरी की विधायिका के प्रति जवाबदेही की प्रतिज्ञा ली।

6.7 क्रांतिकारी आंदोलनों के परिणाम

यूरोप भर में क्रांतिकारी हर्षोन्भाद की स्थिति, और संसदीय सरकार के गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के बावजूद क्रांति अंत में "राजगद्दी के चरणों पर आकर थम गई"। यूरोप के अधिकांश भागों में स्थिति यह रही कि शाही सरकार जस की तस बनी रही और उनके प्रशासनिक ढांचे में भी कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। एक फ्रांस को छोड़कर जहां गणतंत्रीकरण की प्रक्रिया ने कुछ सफलता प्राप्त की, और हर जगह प्राचीन शासन के महत्वपूर्ण राजकीय कर्ता–धर्ता वहीं के वहीं बने रहे। जब अधिकारियों ने सम्राट के मंत्रियों की संसद के प्रति जवाबदेही के सिद्धांत को मान लिया, तब भी शासकों की प्रवृत्ति अपने निजी कर्मचारियों में सत्ता के समानांतर स्रोत बनाने की रही। नागरिकों की सेना गठित करने का क्रांतिकारी सपना तो सपना ही रहा। मताधिकार संबंधी सुधार 1848 की क्रांति की निश्चय ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, किंतु उसका लाभ भी राजनीतिक समानता के पक्षधरों की अपेक्षा यूरोपीय समाज के रूढ़िवादी राजनीतिक गुटों को ही अधिक हुआ। जिस देहाती जनता को वोट देने का नया–नया अधिकार मिला था उन्हें चुनावों का कोई अनुभव तो था नहीं, इसलिए वे जमींदारों के प्रति अपनी पुरानी निष्ठा से ही बंधे रहे। यह सच है कि चुनावों ने राजनीतिक भागीदारी के और भी अधिक अवसर दिए; उन्होंने यूरोपीय समाज के लोकतांत्रीकरण की आकांक्षाओं में अधिक योगदान नहीं दिया। फ्रांस में, संविधान सभा के चुनाव अत्यंत व्यापक मताधिकार के आधार पर हुए किंतु लोकतंत्र की इस परीक्षण प्रक्रिया का परिणाम तो लोकतंत्र के समर्थकों और इसके लाभान्वितों के बीच एक विचित्र प्रकार की विसंगति के रूप में सामने आया। फ्रांस सहित यूरोप में हर कहीं रूढ़िवादी विचारों वाले अनेक प्रत्याशी इसलिए चुनाव जीत गए क्योंकि उन्हें देहाती चुनाव क्षेत्रों में किसानों का समर्थन प्राप्त था। अधिक से अधिक व्यापक मताधिकार की हमेशा ही मांग करने वाले लोकतंत्र समर्थक उग्रपंथियों को उसी मताधिकार के चलते भारी पराजय का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने वकालत की थी।

मध्य 1848 से उदारवादियों के किंचित कमजोर पड़ जाने के साथ ही क्रांति की जड़ें कमजोर होने लगीं। 1848 का उत्तरार्ध पदीय व्यवस्था की वापसी का काल रहा। एक के बाद एक हुए कई नाटकीय टकरावों में क्रांतिकारी शक्तियां पराजित हो गई। उदारवादी आंदोलन के भीतर जो नरमपंथी गुट थे उन्होंने रूढ़िवादियों, राजतंत्र समर्थकों के साथ समझौते का तरीका निकाल लिया और उनके साथ मिलकर 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह के दूसरे दौर को दबाने में निर्णायक भूमिका निभाई। यह चक्र रोके नहीं रूक सका। उदाहरण के लिए, नेपल्ज में जब क्रांतिकारियों ने विदेशी नीति पर संसद के और अधिक नियंत्रण की मांग इसलिए उठाई कि उत्तरी इटली में आस्ट्रीआइयों के खिलाफ नेपल्ज की सेनाओं को तैनात किया जा सके तो सम्राट फर्डिनैंड ने बदले की कार्रवाई में दमन चक्र चलाने का निर्णय किया। उसके बाद सड़कों पर जो लड़ाई हुई तो नेपल्ज के अनियमित राजभक्त मजदूरों 'लादजारॉनी' ने अपने शासकों का समर्थन किया। जून के महीने में पेरिस में दक्षिणपंथ की ओर झुकाव स्पष्ट दिखाई दिया। इससे पहले अप्रैल में कुछ क्रांतिकारियों ने जाने माने समाजवादी लूई ब्लां की सामाजिक कार्यशालाओं की स्थापना की। इन कार्यशालाओं के रखरखाव में कामचलाऊ सरकार को जो अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ा उसके कारण हुए वित्तीय संकट की वजह से फ्रांस के कुछ देहाती क्षेत्रों में करों को लेकर दंगे भड़क उठे, और गणतंत्रवादी वामपंथ के विरूद्ध रूढ़िवादियों के प्रचार में यह एक प्रमुख मुद्दा बन गया। मई के अंत तक, कामचलाऊ सरकार ने इन कार्यशालाओं को बंद करने का निर्णय कर डाला। यह जून के प्रारंभ में अधिकाधिक आक्रामक प्रतिपक्ष के ध्यान का केंद्र बन गया, जब गणतंत्र को अपने समर्थकों के ही विद्रोह का सामना करना पड़ा। कामचलाऊ सरकार ने भीषण दमन किया। तोपखाने के इस्तेमाल समेत जो

दमनकारी कदम उठाए गए वे स्पष्ट रूप मे निम्न वर्गों के विरूद्ध थे और उन्हें पेरिस के समाज के धनिक वर्गों का समर्थन प्राप्त था। इसी से कार्ल मार्क्स को फ्रांस में वर्ग संघर्ष के बारे में एक निश्चित दृष्टिकोण बनाने का अवसर मिला। जून के दिनों की पेरिस की घटनाएं निश्चित रूप मे फ्रांस में वामपंथियों की हार की सूचक थी।

अगस्त 1848 तक हाप्सबर्ग साम्राज्य अपनी कुछ महीने पहले की असहाय स्थिति से उबरने लगा। उत्तरी इटली का अधिकांश भाग जीत लिया गया। सम्राट और उसका दरबार एक बार फिर वीएना में बैठे एक संविधान सभा के साथ भविष्य के बारे में विचार–विमर्श कर रहे थे। केवल हंगरी ही अड़ा रहा। आस्ट्रिआई राजतंत्र की स्थिति में आया यह बदलाव पेरिस के जून के दिनों से कम महत्वपूर्ण नहीं था। राजतंत्र की सत्ता को वापस लाने की प्रक्रिया में साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में क्रांति का विधिवत दमन किया गया। बोहिमिया प्रांत में जर्मन और चेक राष्ट्रवादियों के बीच बैर के कारण प्राग की सैनिक टुकड़ी के सेनापति प्रिंस ऐल्फ्रेड विंडिशग्रेत्स को मार्शल लॉ लागू करने और प्राग राष्ट्रीय समिति को भंग करने का आदेश देने का मौका मिल गया। दक्षिणी यूरोप में, जनरल रायेत्सकी की सेनाओं को उत्तरी इटली में मिली विजय साम्राज्य के बने रहने के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक निर्णायक सैनिक विजय थी। पीडमांट के राजतंत्र ने जिस प्रकार आस्ट्रीआई सेनाओं को घेरने में हिचकिचाहट दिखाई, उससे अंत में इतालवियो को पराजय का मुंह देखना पड़ा। जुलाई 1848 में कूसतॉदजा की निर्णायक लड़ाई में, पीडमांट की सेना बुरी तरह से रौंद दी गई, और उत्तरी इटली में जिन गणतंत्रवादी शासनों की स्थापना की गई थी उसके आत्म समर्पण की राह को रोड़ा हट गया। अगस्त के प्रारंभ में मीलान का पतन हो गया। पीडमांट और आस्ट्रीया के बीच एक संधि हुई और उसके अनुसार उस क्षेत्र के ऊपर आस्ट्रीया का कब्जा बना रहा। 1849 में, पोप की अधीनता वाले राज्यों में एक क्रांतिकारी विद्रोह के बाद भी ऐसी ही घटनाएं हुई जब क्रांतिकारियों के एक गुट ने रोमन गणतंत्र की घोषणा कर दी। ये क्रांतिकारी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक जन आंदोलन के लिए नई रणनीति बना रहे थे। लोकतंत्र समर्थकों ने पीडमांट के राजतंत्र पर इस बात के लिए दबाव बनाया कि वह आस्ट्रीया के साथ नए सिरे से युद्ध करे। जून 1849 में, आस्ट्रीया और पीडमांट की सेना के बीच हुए युद्ध का अंत नोवारो की लड़ाई में पीडमांट की करारी हार के साथ हुआ। पीडमांट के राजा कार्लोस आल्बेतॉ ने विक्टर इमैनुएल के पक्ष में अपनी गद्दी छोड़ दी। विक्टर ने प्रकट तौर पर अपने शासित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक आंदोलनों को दबाने की हामी भर ली थी। पोप ने इससे पहले रोम से भाग कर सिसिली में शरण ले ली थी, और उसे फ्रांसीसी राष्ट्रपति लूई नेपोलियन बोनापार्ट की सेना के संरक्षण में वापस उसके पद पर बैठाया गया।

इटली में मिली सफलता ने आस्ट्रिआइयों को अपनी इच्छा हंगरी की राष्ट्रीय असेम्बली पर थोपने को प्रोत्साहित किया, जबकि असेम्बली पहले ही क्रोएट जैसी छोटी राष्ट्रीयताओं के इरीडेंटिज्म से बहुत त्रस्त हो चुकी थी। इसी संदर्भ में वीएना ने अपना कब्जा वापस लेने की योजना बनाई। बुडापेस्ट में हंगरी की सरकार को आदेश मिला कि वह एक स्वाधीन हंगरी सेना की अपनी योजनाओं को छोड़ दे। आस्ट्रीआई अधिकारियों ने भी परोक्ष रूप से क्रोएट काउंट येलाचिच को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया की वह हंगरी की सरकार के विरूद्ध सैनिक कार्रवाई करे। येलाचिच की सेनाओं ने क्रोएशिया और हंगरी की सीमा को पार किया तो हंगरी की सरकार को तीन मोर्चों पर युद्ध का सामना करना पड़ा। मैगयार संविधानवादी अब भी आस्ट्रीआई साम्राज्य के साथ जुड़ने की आशा बाधे हुए थे, और आस्ट्रीयाई चालों ने अब उनकी साख गिरा कर रख दी। बुडापेस्ट के क्रांतिकारियों ने इस स्थिति का जवाब देने की मांग की और लॉयोश कोशूट के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय रक्षा समिति की नियुक्ति कर दी। कोशुट तो हाप्सबर्ग के निरंकुश राज्य के प्रति हंगरी के प्रतिरोध का पुराना नेता था। इस मामले में हंगरी की सरकार से कोई मशवरा नही किया गया। कुछ दिनों बाद, वीएना के अधिकरियों ने हंगरी की सरकार और संसद को भंग कर दिया, जिससे संविधानवादी मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ा और राष्ट्रीय रक्षा समिति के साथ टकराव की स्थिति बन गई। सैनिक संघर्ष के शुरुआती दौर में हंगरी सफल रहा; किंतु अंत में, रूस के सहयोग से हंगरी के राष्ट्रवादी प्रतिरोध को दबा दिया गया।

जर्मनी में, राष्ट्रीय एकीकरण के उदारवादी कार्यक्रम को पहले ही धक्का लग चुका था। अगस्त में विद्रोही वीएना की जीत, और प्रशा में नवम्बर के संकट के चलते जर्मन राष्ट्रीय सरकार की योजना ध्वस्त हो गई। प्रशा के निरंकुश राज्य के बारे में अत्यंत सहनशीलता का परिचय देने वाली फ्रैंकफर्ट राष्ट्रीय असेम्बली अब महत्वपूर्ण नहीं रह गई क्योंकि प्रशा के सम्राट ने इसका नेतृत्व करने से मना कर दिया और असेम्बली में प्रशा समर्थक संविधानवादी राजतंत्र समर्थकों के पास आस्ट्रीया के बिना एक जर्मन राष्ट्रीय राज्य बनाने का कोई साधन नहीं रह गया। इस बीच प्रशा की संविधान सभा प्रशा के सम्राट के लिए खतरा बन चुकी थी। गणतंत्रवादी तो अल्पमत में थे, किंतु संविधानवादी राजतंत्र

समर्थक एक जबरदस्त ताकत के रूप में विद्यमान थे। प्रशा के राजतंत्र के लिए यह अहम बात थी कि वह इस प्रतिपक्ष से निर्णायक तौर पर निपटे और सम्राट ने नवम्बर 1848 में ठीक यही किया। उसने इसके लिए अति राजतंत्र समर्थक प्रधानमंत्री काउंट ब्राडनबर्ग के दमनकारी कदमों को माध्यम बनाया। ब्राडनबर्ग ने एकतरफा तौर पर एक संविधान की घोषणा कर दी, जबकि संविधान सभा की बहस चलती ही रही। इस प्रकार, प्रशा के रूढ़िवादियों ने अपने पारंपरिक विचारों का 1848 की बदली हुई राजनीतिक स्थितियों के अनुरूप ढाल लिया। बहरहाल, राजतंत्र समर्थकों ने प्रशा में एक नया संविधान स्थापित करके अंततः क्रांतिकारियों पर विजय प्राप्त कर ली। किंतु, दक्षिणी–पश्चिमी जर्मनी में संविधानवादी शासन अस्तित्व में बने रहे, और 1871 में एकीकरण होने से पहले के दशकों में उदारवादी राष्ट्रवादियों को प्रेरणा देते रहे।

वर्ष 1848-49 की यूरोप की क्रांतिकारी घटनाओं की कहानी में, क्रांतिकारी सेनाओं की अंतिम हार फ्रांस में हुई। दिसम्बर 1848 में, लूई नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का राष्ट्रपति चुन लिया गया। उसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए रखे गए अतिशय कार्यकारी अधिकार मिले। बोनापार्ट की सफलता के पीछे किसानों का बेसमझी भरा समर्थन और राजतंत्र सर्मथकों का प्रत्याशित आत्म संतोष रूपी एक बड़ा कारण रहा। उस समय तक तो फ्रांसीसी बुर्जुआ वर्ग क्रांति की उथल–पुथल से तंग आ चुका था, जल्दी ही वह भी लूई नेपोलियन के तानाशाही दिखावों से तालमेल बैठा कर चलने लगा। 1849 के मध्य में, उग्रपंथ के अंतिम सूत्रों के दमन के साथ ही क्रांति के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया। यह केवल फ्रांस ही नहीं, अपितु यूरोप में और जगहों पर भी हुआ। दिसम्बर 1851 को नेपोलियन के तख्ता पलटने के बाद जिस जनमत ने उसके आजीवन राष्ट्रपति होने पर मुहर लगा दी, वह पराजय की कहानी का उपयुक्त अंत था।

बोध प्रश्न 3

1) वर्ष 1848 की क्रांति के पीछे के आर्थिक संकट को पांच वाक्यों में समझाइए।

....

....

....

....

....

2) वर्ष 1848 की क्रांति का हाप्सबर्ग साम्राज्य पर क्या असर पड़ा ? 50 शब्दों में बताइए।

....

....

....

....

....

....

3) क्या 1848 की क्रांति फ्रांस में सफल रही ? पांच वाक्यों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

....

6.8 सारांश

इस इकाई में आपने महाशक्तियों द्वारा कांग्रेस प्रणाली को विकसित करने के बारे में पढ़ा। उनका जोर प्राचीन व्यवस्था की बहाली पर था। किंतु, यह उनका दुर्भाग्य रहा कि उदारवाद और राष्ट्रवाद के विचार लोगों को पहले ही प्रभावित कर चुके थे। गुप्त संगठन आंदोलनों और यूरोप के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी विद्रोहों में प्राचीन व्यवस्था क पुनर्स्थापन के प्रति आम रूझान की अभिव्यक्ति हुई। 1815 में शासन–क्षेत्रों को लेकर समझौते हुए। 1848 की यूरोप की क्रांतिकारी घटनाओं ने संसदीय सरकार पर ध्यान तो केंद्रित किया किंतु वे राजतंत्रीय सरकार के चरित्र को अधिक बदल नहीं सकी। यहां तक कि फ्रांस में भी क्रांतिकारी शक्तियां लूई नेपोलियन की तानाशाही को उभरने से रोक नहीं पाई।

6.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) शक्ति–संतुलन बनए रखने के लिए, शांति के लिए, राजतंत्रीय शासन की बहाली के लिए, आदि। देखिए भाग 6.2
2) महाशक्तियों के बीच हितों की टकराहट, उदारवाद एवं राष्ट्रवाद का प्रभाव, संवैधानिक राजतंत्र की बढ़ती मांग, आदि । देखिए भाग 6.2
3) देखिए भाग 6.3

बोध प्रश्न 2

1) देखिए भाग 6.4
2) देखिए भाग 6.4
3) देखिए भाग 6.5

बोध प्रश्न 3

1) बढ़ती गरीबी, बिचौलियों द्वारा अत्याचार, कारखानों के सस्ते उत्पादनों से होड़ के कारण कारीगरों व दस्तकारों में क्षोभ, आदि। देखिए भाग 6.6
2) देखिए भाग 6.7
3) देखिए भाग 6.7